नागरिक विविध

न्यायमूर्ति टेक चंद के समक्ष

देवी चंद-.याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सिविल रिट 1967 की संख्या 1434

नवंबर 24, 1967

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966 का XXXI)—एस.एस. 82 और 83 - नियत दिन से ठीक पहले चंडीगढ़ में पंजाब रोडवेज में सेवारत व्यक्ति - जिस राज्य में उसे आवंटित किया जा सकता है।

माना गया कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 के प्रावधानों के आधार पर, याचिकाकर्ता जो नियत दिन से ठीक पहले मौजूदा पंजाब राज्य की सेवा कर रहा था, उसे नए राज्य में अनंतिम रूप से सेवा जारी रखनी थी। पंजाब, जब तक कि उसे केंद्र सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कहीं और सेवा करने की आवश्यकता न हो। धारा 82(1) की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए आवंटित व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वह हजारों अन्य लोगों के साथ, नियुक्ति से ठीक पहले चंडीगढ़ में सेवा कर रहा था। दिन। उनका उचित आवंटन पंजाब राज्य में है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रत्युत्तर संख्या 3 और 4 के आदेशों को रद्द करते हुए सर्टिओरारी, परमादेश या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिससे याचिकाकर्ता को राहत मिले। उनकी डिटिज और बाद में उनकी सेवा पहले पंजाब राज्य और फिर हिमाचल प्रदेश को आवंटित की गई।

वकील आर. पी. बाली याचिकाकर्ता की ओर से

आनंद स्वरूप एडवोकेट-जनरल (हरियाणा) और एडवोकेट ए.एस. बैंस, एडवोकेट, एडवोकेट-जनरल (पंजाब) प्रतिवादियों की ओर से।

आदेश

टेक चंद, जे.-यह रिट याचिका है और प्रतिवादी हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य, प्रांतीय परिवहन नियंत्रक और महाप्रबंधक हैं। हरियाणा, रोडवेज, चंडीगढ़

याचिका को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता देवी चंद पंजाब राज्य के पुनर्गठन से पहले चंडीगढ़ में पंजाब रोडवेज के महाप्रबंधक के अधीन लोहार के रूप में कार्यरत थे। पुनर्गठन से पहले वह लगभग तीन वर्षों तक सेवा में थे। याचिका में कहा गया है कि पुनर्गठन के बाद, उनकी सेवाएं हरियाणा राज्य को आवंटित की गईं और प्रतिवादी संख्या 4 ने उन्हें उस राज्य में तैनात किया था जहां उन्होंने डेढ़ महीने की अवधि के लिए काम किया था। लगभग छह सप्ताह तक सेवा देने के बाद, उन्हें हरियाणा के अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है और चूंकि उनका आवंटन पंजाब राज्य में था, इसलिए उन्हें पंजाब रोडवेज के महाप्रबंधक को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने खुद को चंडीगढ़ में पंजाब रोडवेज के महाप्रबंधक के पास ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया,लेकिन बाद ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे वापस महाप्रबंधक,हरियाणा रोडवेज(प्रतिवादी नं 4)को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। कोई न कोई रास्ता तय करने के बजाय,हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक ने काफी समय तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। याचिकाकर्ता ने प्रांतीय परिवहन नियंत्रक,हरियाणा(प्रतिवादी संख्या 3)को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस अधिकारी ने याचिकाकर्ता को संयुक्त प्रांतीय परिवहन नियंत्रक, हरियाणा के पास भेज दिया। 28 दिसंबर,1966 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को संयुक्त प्रांतीय परिवहन नियंत्रक, हरियाणा द्वारा खुद को महाप्रबंधक, हिमाचल सरकारी परिवहन, शिमला को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया,इस आधार पर कि उनकी सेवाएं हिमाचल को आवंटित की गई थीं। प्रदेश संयुक्त प्रान्तीय परिवहन नियंत्रक के आदेश की प्रति हरियाणा, अनुलग्नक 'ए' है और निम्नलिखित प्रभाव वाला है:-

“श्री देवी चंद, लोहार, जिन्हें 17 दिसंबर, 1966 (पूर्वाह्न) से अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है, को पहले ही स्थानांतरित किए गए वाहनों के साथ हिमाचल प्रदेश को सौंपे गए वर्कशॉप स्टाफ के मुकाबले हिमाचल राज्य को आवंटित किया जाता है। वह शायद कर सकता है। इसलिए, उसकी सेवा में व्यवधान से बचने के लिए उसका मनोरंजन किया जाए।”

इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि संयुक्त प्रांतीय परिवहन नियंत्रक,हरियाणा द्वारा इस आदेश को उचित ठहराने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। कहा गया है कि ऐसा गलती से हुआ होगा, हरियाणा के संयुक्त प्रांतीय परिवहन नियंत्रक के इस आदेश के साथ, याचिकाकर्ता ने खुद को शिमला में हिमाचल सरकार परिवहन के महाप्रबंधक के सामने प्रस्तुत किया,लेकिन बाद वाले ने याचिकाकर्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे निर्देश दिया कि

संयुक्त प्रांतीय परिवहन नियंत्रक, हरियाणा को रिपोर्ट करें, लेकिन कहा जाता है कि वह लंबे समय तक चुप रहे। याचिकाकर्ता को हरियाणा के अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उसने प्रांतीय परिवहन नियंत्रक, हरियाणा (प्रतिवादी नंबर 3) को 17 फरवरी, 1967 और 25 मार्च, 1967 को दो आवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन वह भी चुप रहे और कोई आवेदन पारित नहीं किया। आदेश देना। इन आवेदनों की प्रतियां क्रमशः 'बी' और 'सी\' हैं।

याचिकाकर्ता ने 25 मार्च 1967 को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया सचिव, परिवहन, हरियाणा, और उन्होंने प्रतिवादी संख्या 3 की टिप्पणियों के लिए बुलाया, लेकिन ऐसी कोई टिप्पणी नहीं भेजी गई और याचिकाकर्ता को उनके प्रतिनिधित्व के भाग्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 9 मई, 1967 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 1, हरियाणा राज्य और प्रतिवादी नंबर 3, प्रांतीय परिवहन नियंत्रक, हरियाणा को न्याय की मांग करते हुए एक नोटिस प्रस्तुत किया गया था। प्रांतीय परिवहन नियंत्रक, हरियाणा ने सचिव, हरियाणा, परिवहन विभाग को एक पत्र लिखा, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता के वकील को भी भेजी गई, जिसमें कहा गया कि श्री देवी चंद को पंजाब रोडवेज को आवंटित किया गया था और इस मामले में, उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था। पंजाब रोडवेज के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। उन्हें समाहित करने की जिम्मेदारी पंजाब राज्य की थी।

याचिकाकर्ता, जिसे दर-दर भटका दिया गया है, व्यथित महसूस करता है और उसने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत निवारण की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की है और अपने आवंटन के संबंध में एक उपयुक्त रिट या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है। एक तथ्य यह है कि उन्हें 17 दिसंबर, 1966 को कार्यमुक्त कर दिया गया था, और तब से उन्हें कोई वेतन या परिलब्धियां नहीं दी गई हैं, और संबंधित प्रशासन, जिसे भी उन्होंने सहायता के लिए आवेदन किया था, ने जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के साथ उसके हितों, अधिकारों या भावनाओं की घोर उपेक्षा करते हुए अपमानजनक व्यवहार किया गया है। उनके आचरण पर कोई दोष नहीं लगाया गया है. वह तब तक ईमानदारी से प्रशासन की सेवा करते रहे जब तक उन्हें पता नहीं चला कि 17 दिसंबर, 1966 को अचानक उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया। जब भी उन्होंने राहत मांगी, उन्हें दूसरे प्रशासन को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। यहां तक कि उन्हें हिमाचल प्रदेश प्रशासन को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया, हालांकि उन्हें वहां भेजने का कोई आधार नहीं था।

अब यह मान लिया गया है कि यह सब कुछ संबंधित अधिकारियों की गलती के कारण हुआ। किसी भी प्रशासन में किसी को भी इस पीड़ा और उत्पीड़न का एहसास नहीं हुआ

याचिकाकर्ता को उसकी किसी भी गलती के बिना दंडित किया गया था। कोई भी उन्हें एक राज्य या दूसरे राज्य में आवंटित करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ग्यारह महीने से अधिक समय से उन्हें वेतन या अन्य परिलब्धियों के रूप में कुछ भी नहीं मिला था। हरियाणा राज्य का तर्क यह है कि गलती के कारण उन्हें उस प्रशासन के तहत डेढ़ महीने तक काम करने की अनुमति दी गई थी और उनके आवंटन के अनुसार उन्हें पंजाब राज्य में नियुक्त किया जाना चाहिए था। उनके प्रति पंजाब प्रशासन का रवैया भी उतना ही निषेधात्मक रहा है। एक शटल-कॉक की तरह, उसे हरियाणा और पंजाब और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के बीच इधर-उधर घुमाने के लिए मजबूर किया गया है। मुख्य प्रश्न उसके आवंटन के स्थान का है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1986 की धारा 82, उपधारा (1) प्रदान करती है: -

“82. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन से ठीक पहले मौजूदा पंजाब राज्य के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है, उस दिन से, अनंतिम रूप से पंजाब राज्य के मामलों के संबंध में सेवा करना जारी रखेगा। जब तक कि उसे केंद्र सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी अन्य उत्तराधिकारी राज्य के मामलों के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा करने की आवश्यकता न हो।

इस प्रावधान के अवलोकन से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि याचिकाकर्ता को पंजाब राज्य में अस्थायी रूप से सेवा करनी थी, जब तक कि उसे केंद्र सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कहीं और सेवा करने की आवश्यकता न हो। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। धारा 82(1) के प्रावधानों के मद्देनजर, पंजाब राज्य याचिकाकर्ता को समाहित करने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता।

अनुलग्नक आर-एल बहत्तर कर्मचारियों से संबंधित "पंजाबी सूबा के लिए कार्यशाला कर्मचारियों के आवंटन" का एक विवरण है। याचिकाकर्ता क्रमांक 24 पर है। बयान पर पंजाब और हरियाणा रोडवेज और चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम के महाप्रबंधकों के हस्ताक्षर हैं। यह विवरण 27 अक्टूबर, 1966 का है। इसके अवलोकन से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि याचिकाकर्ता को पंजाब राज्य आवंटित किया गया था। श्री नौनिहाल सिंह के हस्ताक्षर से हरियाणा रोडवेज, चंडीगढ़ के लिए वर्कशॉप स्टाफ के आवंटन के एक अन्य विवरण द्वारा भ्रम पैदा किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 22 पर दिखाया गया है। इस प्रकार एक बयान में श्री नौनिहाल सिंह के हस्ताक्षर हैं याचिकाकर्ता को हरियाणा रोडवेज को आवंटित किया गया है और दूसरे बयान में भी श्री नौनिहाल के हस्ताक्षर हैं

सिंह और दो अन्य अधिकारियों द्वारा, उन्हें पंजाब राज्य को आवंटित किया गया है। आपस में प्रशासन, उस दुविधा से अवगत होने के बाद जिसमें याचिकाकर्ता ने खुद को पाया था, एक सहमत समझौते पर नहीं आ सका कि याचिकाकर्ता को कहाँ अवशोषित किया जाना चाहिए था। ऐसा कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता कि याचिकाकर्ता के आवंटन के बारे में निर्णय समय पर क्यों नहीं लिया जा सका और यदि दोनों प्रशासनों के बीच कोई मतभेद था, तो उसे शीघ्रता से हल नहीं किया जा सका। यह अत्यंत कठिन मामला है और इसमें उदासीनता बरतने वालों की जिम्मेदारी है! याचिकाकर्ता के साथ किए गए अनुत्तरदायी व्यवहार को दोनों राज्य सरकारों के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा साझा किया जाना चाहिए। वे एक वर्ष के भीतर जो निर्णय नहीं ले सके, उसके लिए अधिनियम की धारा 82 और 83 और आवंटन की पारस्परिक रूप से सहमत सूची पर एक नज़र डालने से अधिक की आवश्यकता नहीं थी, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम पंजाब के लिए नियुक्त कर्मचारियों में शामिल था।

वकील की दलीलें सुनने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को जिस राज्य में आवंटन किया जा सकता था वह पंजाब राज्य था, न कि हरियाणा राज्य। इस स्तर पर अधिनियम की धारा 83 का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जो अधिकारियों को समान पद पर बने रहने का प्रावधान है। यह प्रदान करता है : -

"83. प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन से ठीक पहले पंजाब के मौजूदा राज्य के मामलों के संबंध में किसी भी क्षेत्र में किसी भी पद या कार्यालय को धारण या कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जो उस दिन किसी भी उत्तराधिकारी राज्य के अंतर्गत आता है, वह पद पर बना रहेगा। उस उत्तराधिकारी राज्य में वही पद या कार्यालय और उसी दिन से, उस राज्य की सरकार या अन्य द्वारा उस पद या कार्यालय पर विधिवत नियुक्त किया गया माना जाएगा। उस उत्तराधिकारी राज्य में उपयुक्त प्राधिकारी:

बशर्ते कि इस धारा में किसी भी बात को सक्षम प्राधिकारी को नियत दिन पर या उसके बाद ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऐसे पद या कार्यालय में उसकी निरंतरता को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश को पारित करने से रोकने वाला नहीं माना जाएगा।

नियत दिन से ठीक पहले, याचिकाकर्ता चंडीगढ़ में मौजूदा पंजाब राज्य के मामलों के संबंध में अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। धारा 2(m) मौजूदा पंजाब राज्य के संबंध में "उत्तराधिकारी राज्य" को परिभाषित करती है

जिसका अर्थ है "पंजाब या हरियाणा राज्य, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हस्तांतरित क्षेत्र के संबंध में केंद्र भी शामिल है"। धारा 82(1) की स्पष्ट भाषा को देखते हुए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि याचिकाकर्ता को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए आवंटित व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वह हजारों अन्य लोगों के साथ पहले चंडीगढ़ में सेवा कर रहा था। मेरे विचार से उनका उचित आवंटन पंजाब राज्य में है। वह 17 दिसंबर, 1966 से पंजाब राज्य से अपना वेतन और परिलब्धियां प्राप्त करने का हकदार है।

रिट याचिका स्वीकार की जाती है और पंजाब राज्य को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को उस राज्य को आवंटित माना जाए और उसे 17 दिसंबर, 1966 से उसका बकाया भुगतान किया जाए। उसे पहले ही एक महीने का वेतन मिल चुका है, आधे हरियाणा प्रशासन में सेवा करते हुए। याचिकाकर्ता अपनी लागत का भी हकदार है, जिसका मूल्यांकन 200 रुपये किया गया है, जिसका भुगतान पंजाब राज्य द्वारा किया जाएगा।

B. R. T.

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा